ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

12 सितम्बर, 2018 • वर्ष 1, अंक 34

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
शिक्षक दिवस के अवसर पर 'राज्य अध्यापक पुरस्कार समारोह' के दौरान शिक्षकों का सम्मान करते हुए

• औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान • लघु एवं मध्यम उद्यमियों को उद्यम स्थापना पर 20 लाख तक की छूट
• बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचा रही है सरकार • ग्रामीणों के जीवन को नई दिशा देंगे ग्राम विकास अधिकारी
• निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों को हर संभव सहयोग • प्रजापति समाज को डिजाइन और ब्राण्डिंग का प्रशिक्षण

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचा रही है सरकार

बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से सहायता करने तथा बाढ़ के स्थायी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां आवश्यकता हो, वहां बांध भी बनाए जाएं। नदियों के तटवर्ती गांवों के परिवारों को सुरक्षित जगहों पर बसाया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इस वर्ष भारी वर्षा के बावजूद सरकार द्वारा पहले से काफी प्रयत्न किए गए थे, जिसके फलस्वरूप जन–धन की हानि में काफी कमी आयी है। इस वर्ष पूरे प्रदेश में बाढ़ से काफी कम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

आपदा पीड़ितों को मिल रहा है खाद्यान्न और तिरपाल

जनपद सीतापुर में मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत किट के वितरण के अवसर पर अपने उद्गार व्सयक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर दाल, एक लीटर सरसों का तेल व मसालों के साथ ही 10 किलो आलू, 5 किलो लइया, एक किलो चना, नमक तथा तिरपाल दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अब सर्पदंश से, नाव पलटने से, सीवर सफाई के दौरान या किसी वन्य जीव के हमले में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का कार्य किया जा रहा है।

सीतापुर जनपद की 18 हजार की जनसंख्या तथा 120 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के आवागमन हेतु नावों का संचालन किया जा रहा है। 2800 लोगों को ऊंचे स्थानों पर विस्थापित किया गया है। प्रभावित लोगों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को चिकित्सकीय सहायता तथा पशुओं के चारे व चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है। ■

> **पहले विभिन्न तरह की आपदाओं जैसे– सर्पदंश, गैस रिसाव, नाव दुर्घटना, पशु हानि को दैवीय आपदा नहीं माना जाता था। वर्तमान सरकार द्वारा ऐसी सभी आपदाओं को दैवीय आपदा मानते हुए 04 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।**
>
> **–योगी आदित्यनाथ** मुख्यमंत्री

आपदा राहत के कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं : सीएम

जनपद गोण्डा में बाढ़ पीड़ितों को राहत किट प्रदान करने के पश्चात् अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कार्य तेजी से व संवेदनशीलता के साथ कराए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को हर सम्भव सहायता अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

राहत कैम्पों में जीवनरक्षक दवाओं के साथ–साथ अन्य आवश्यक दवाओं, भोजन, पेयजल, पशुओं के चारे आदि की उपलब्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई गई है। आपदा राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

केन्द्र व प्रदेश सरकार आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे जिस प्रकार की भी आपदा हो सरकार द्वारा हर सम्भव और तत्काल मदद करने का प्रबन्ध किया गया है।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मौनपालन प्रशिक्षण

16 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 2018 तक तीन माह का होगा प्रशिक्षण

सहारनपुर, बस्ती, इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्रों पर कराया जायेगा प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिये वैज्ञानिक पद्धति से मौन (मधुमक्खी) पालन को कृषि एवं बागवानी आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्रों पर दीर्घकालीन मौनपालन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

मौनपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर से 15 दिसम्बर, 2018 तक तीन माह (90 दिवसीय) का प्रशिक्षण सत्र जनपद सहारनपुर, बस्ती, इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्रों पर आरम्भ किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा, लेकिन प्रशिक्षार्थियों को रहने एवं खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस प्रशिक्षण में किसी भी आयु के पुरूष एवं महिलायें भाग ले सकते है। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ग्रामीणों के जीवन को नई दिशा देंगे ग्राम विकास अधिकारी

नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों की ऑन-लाइन जनपद आवंटन प्रणाली प्रारंभ

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम विकास अधिकारियों को प्रदान किये नियुक्ति पत्र

ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण लोगों के जीवन को दिशा दे सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रतिबद्ध होकर प्रयास किए जाने से प्रदेश के सभी गांवों में खुशहाली आ सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से बेघर को घर, शौचालय निर्माण, विद्युत कनेक्शन, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, गरीब परिवारों को राशन, विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में ग्राम विकास अधिकारियों की बड़ी भूमिका है। ग्राम विकास अधिकारी का कार्य बड़ी जिम्मेदारी और पुण्य का कार्य है। ग्राम विकास अधिकारियों को यह अवसर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण मिला है।

यह विचार मुख्यमंत्री जी ने नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों की ऑन-लाइन जनपद आवंटन प्रणाली के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लगभग 30 ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये।

तकनीक से भ्रष्टाचार पर लगाम

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं। तकनीक के व्यापक प्रयोग से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके मद्देनजर वर्तमान राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में तकनीक के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इससे विगत डेढ़ वर्षों में नियुक्तियां स्वच्छता और पारदर्शिता से की गई हैं। इससे प्रदेश के नौजवानों में उत्साह है।

प्रदेश की प्रतिभाओं का पलायन रोकने हेतु प्रयासरत है सरकार

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौजवान हमारे देश की प्रतिभा हैं। यदि इस प्रतिभा का उपयोग नहीं हुआ, तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की प्रतिभाओं को किसी भी स्थिति में पलायन न करना पड़े। इसलिए राज्य सरकार राजकीय तथा निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करा रही है। साथ ही, स्वरोजगार अथवा परम्परागत उद्यमों को विकसित करने में रुचि रखने वाले युवाओं को भी प्रदेश सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। ■

शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का फोकस

वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करके कार्य किया है। इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को समय से सम्पन्न कराया गया है। नकलविहीन परीक्षा कराना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम से इसमें सफलता प्राप्त की गई है। पहली बार हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम समय से तथा एक ही दिन घोषित किए गए हैं। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव लाने में सफल रही है। प्रदेश के शिक्षकों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रौशन किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की होगी नई पहचान

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की विशेष ख्याति रही है। उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो देश भी आगे बढता है। इसलिए सभी शिक्षकगणों को उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में इसकीख्याति को वापस दिलाने का संकल्प लेकर एवं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जा सके।

शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य अध्यापक पुरस्कार समारोह के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए राज्यपाल राम नाईक जी ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयास से राज्य के विश्वविद्यालयों का सत्र एवं शैक्षिक कैलण्डर नियमित हुआ है, इससे प्रदेश के बाहर राज्य की छवि बेहतर हो रही है। शैक्षिक कैलेण्डर के नियमित होने के पश्चात अब राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शोध कार्य बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए।

बालिका सशक्तीकरण के सार्थक परिणाम

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के आकड़े प्रस्तुत करते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा पदक जीतने में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से अधिक है। बालिकाओं के इस सशक्तिकरण में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रारम्भ किए गए 'सर्वशिक्षा अभियान' तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारम्भ की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का बड़ा योगदान है।

राष्ट्र निर्माता है शिक्षक : सीएम

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। उसके आचरण से ही राष्ट्र का आचरण भी निर्धारित होता है। अनुशासित समाज का निर्माण शिक्षा जगत का कर्तव्य है। शिक्षक संकल्प कर लें, तो शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा तमाम वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया गया है। ■

आगामी वर्ष से राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया में बदलाव लाया जाएगा। पुरस्कार हेतु चयन के लिए प्रत्येक अध्यापक को अपने शैक्षिक एवं शिक्षा से इतर कार्यों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण देना होगा। प्रस्तुतिकरण के आधार पर पुरस्कार के लिए शिक्षक का चयन किया जाएगा। इससे पुरस्कृत शिक्षक के अनुकरणीय कार्यों और नवाचारों से शिक्षक समुदाय को अवगत कराकर लाभान्वित किया जाना सम्भव होगा।

निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों को मिलेगा हर संभव सहयोग

वर्तमान राज्य सरकार के सतत प्रयास से उत्तर प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। इससे राज्य में बड़ी संख्या में निवेश के इच्छुक औद्योगिक संस्थान अपने प्रतिष्ठान स्थापित कर रहे हैं। देश और प्रदेश के हित में, राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति या संस्थान प्रदेश में निवेश कर सकता है। प्रदेश सरकार ऐसे निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों को सभी सम्भव सहयोग उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार हॉयर कम्पनी और राज्य सरकार के मध्य एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में हॉयर इण्डिया के प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के 3डी मॉडल का अनावरण किया।

'मेक इन इण्डिया' अभियान को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित कम्पनी के साथ राज्य सरकार का समझौता प्रदेश में औद्योगिक निवेश को एक नए गंतव्य की ओर ले जाएगा। हॉयर कम्पनी द्वारा ग्रेटर नोएडा में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके दो साल से भी कम समय में रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन, टी.वी. आदि का उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मेक इन इण्डिया' अभियान को भी नई गति मिलेगी।

निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विण्डो पोर्टल

राज्य सरकार ने अपने डेढ़ वर्ष के समय में सभी को बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा का वातावरण सुलभ कराया है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए फोकस सेक्टर्स को चिन्हित कर नीतियां बनायी गई हैं। निवेशकों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम भी क्रियाशील किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा निवेश गंतव्य है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए युग की शुरूआत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य में औद्यागिक विकास का नया युग शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए हर सम्भव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश निवेश का ग्लोबल हब बन गया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आदि देशों की कम्पनियों उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। ■

ईंधन के रूप में प्रयुक्त फर्नेस आयल और पेट कोक पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले फर्नेस आयल और पेट कोक को प्रतिबंधित करते हुए तीन माह (31 दिसम्बर, 2018) के उपरांत इनका प्रयोग सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिषिद्ध कर दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति 31 दिसम्बर 2018 के उपरांत फर्नेस आयल और पेट कोक का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध समुचित विधिक कार्यवाही की जायेगी।

ईंधन के रूप में फर्नेस आयल और पेट कोक के प्रयोग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचता है और जनसामान्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। एन.सी.आर. क्षेत्र के अधीन आने वाले भाग में इनका प्रयोग पूर्व में ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।

सोशल मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुंचेगी सरकार की योजनाएं

सोशल मीडिया वर्तमान समय की आवश्यकता है इसके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को आमजन तक शीघ्रता से पुहंचा सकती है। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार वाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। राज्यस्तर तथा जिलास्तर पर इन सोशल मीडिया ग्रुपों से लोगों को जोड़ा जाएगा। ट्विटर पर शासकीय जानकारी त्वरित रूप से पोस्ट की जाएगी। ओ.डी.एफ. तथा आयुष्मान भारत के लिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सूचना विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला सूचना कार्यालयों का निर्माण जिलाधिकारी कार्यालय के नजदीक कराया जाएगा और जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण शीघ्र किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सक्सेस स्टोरीज़ को व्यापक स्तर पर प्रसारित करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मीडिया में उन्हें स्पेस मिले। सक्सेस स्टोरीज़ का प्रेज़ेण्टेशन और भी उत्कृष्ट बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभाग को उच्चीकृत करते हुए उपलब्ध तकनीक का सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं इत्यादि के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। मुम्बई सहित देश के अन्य महानगरों में भी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। सूचना विभाग द्वारा जारी किए जा रहे प्रेसनोटों इत्यादि में तथ्यपरक कन्टेंट का इस्तेमाल होगा। विभाग द्वारा फोटोज़ और वीडियोज़ की एक लाइब्रेरी स्थापित की जायेगी। फिल्म बन्धु के समक्ष फिल्म निर्माण से सम्बन्धित जो भी प्रस्ताव हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

प्रजापति समाज को मिलेगा डिजाइन और ब्राण्डिंग का प्रशिक्षण

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रजापति समाज बाहुल्य इलाकों के निकटस्थ तालाबों का पट्टा अप्रैल से जून के मध्य प्रजापति समाज के लोगों को दिया जाएगा। इससे प्रजापति समाज को मिट्टी उपलब्ध हो जाएगी, साथ ही जल संरक्षण हेतु भी तालाब तैयार हो जाएंगे।

प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा मानदेय

मुख्यमंत्री जी ने कुम्हार–शिल्पकार समाज की मांगों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में कहा कि प्रजापति समाज के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें तकनीक, डिजाइन, मार्केटिंग, ब्राण्डिंग आदि का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिए मानदेय की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें आवश्यक टूल किट्स निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षित लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोड़ा जाएगा।

पॉलीथीन पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्लास्टिक, थर्मोकोल एवं पॉलीथीन की वस्तुओं पर सख्ती से रोक लगायी जाएगी। सरकारी कार्यालयों एवं अन्य राजकीय संस्थाओं को कुल्हड़ आदि मिट्टी के उत्पादों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग के स्टोरों में 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना के उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी।

बेहतर आवागमन के लिए मेट्रो आज की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने किया लखनऊ मेट्रो के मोबाइल ऐप और शुभांकर का लोकार्पण

बेहतर आवागमन के लिए मेट्रो आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम कम समय में आनन्ददायक यात्रा की सुविधा प्राप्त करते हैं। समय की बचत करके ही हम विकास के सहभागी बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार लखनऊ मेट्रो रेल सेवा की प्रथम वर्षगांठ पर आज यहां आयोजित लखनऊ मेट्रो दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किए।

आने वाली पीढ़ी को बेहतर यातायात की सुविधा

उन्होंने कहा कि जीवन में सदैव नवीनता को स्वीकार करना चाहिए। मेट्रो की सोच आगामी 50 और 100 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ मेट्रो मोबाइल एप का शुभारम्भ भी किया। इस एप के माध्यम से आमजन को मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी।

35 लाख यात्री जुड़े लखनऊ मेट्रो से

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ मेट्रो ने मात्र एक वर्ष में आम लोगों को अच्छी सुविधाओं व वातावरण के बीच यात्रा सुलभ करायी है। इस सेवा से लगभग 35 लाख यात्रियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेट्रो रेल के द्वितीय चरण का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। मेट्रो रेल सेवा अपनी अनुशासन प्रियता के लिए काफी लोकप्रिय है।

इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ मेट्रो के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित मेट्रो स्टेशन के लिए चारबाग मेट्रो स्टेशन को पुरस्कृत किया गया।

कानपुर, आगरा और प्रदेश के अन्य शहरों में भी शीघ्र होगा मेट्रो का संचालन

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के अन्दर लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में सफलतापूर्वक मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। आने वाले समय में कानपुर, आगरा, और मेरठ में भी इसका संचालन किया जाएगा। इसके लिए इन परियोजनाओं की डी.पी.आर. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं। जब लखनऊ मेट्रो रेल का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा, तब शहर की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी।

11 सितम्बर 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को सातवां वेतनमान

प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी आय स्वयं करते हैं और प्राधिकरणों में केन्द्रीयत सेवा नियमावली 2018 लागू होने के उपरान्त सभी प्राधिकरणों के कार्मिकों को एक समान वेतन देने हेतु सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2016 से प्राधिकरणों में लागू कराने का निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरणों को स्वयं करना होगा खर्च का वहन

सातवां वेतनमान लागू होने के उपरान्त आने वाले अतिरिक्त भार को प्राधिकरण अपने स्रोतों से वहन करेगा, राज्य सरकार प्रारंभ में अथवा भविष्य में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

लघु एवं मध्यम उद्यमियों को उद्यम स्थापना पर 20 लाख तक की छूट

'एक जिला एक उत्पाद' योजना के अन्तर्गत उद्यम स्थापित करने वाले लघु तथा मध्यम उद्यहिमयों के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट की लागत के अनुसार 6.25 लाख से लेकर 20 लाख रूपये तक की छूट देने का निर्णय लिया है। ओडीओपी से बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावनाओं के दृष्टिगत सरकार ने यह निर्णय लिया है।

लागत के अनुसार होगी मार्जिन मनी

- 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो कम हो।
- 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक की लागत वाली इकाइयों के लिए 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो अधिक हो)।
- 50 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ तक की लागत वाली इकाइयों पर 10 लाख रुपये या लागत का 15 प्रतिशत (जो अधिक हो)।
- 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये (जो कम हो)।

मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर रखे जाएंगे रिटायर्ड प्रोफेसर

प्राचार्य बनने हेतु पीएचडी के प्रकाशन की अनिवार्यता होगी समाप्त

सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित हुईं कंसल्टेंट की दरें

गोरखपुर में होगी एडवांस फोरेंसिक लैब की स्थापना

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी